

नये साल में लगेगा

मंहवाई का

करंट

महंगे हो जाएंगे कपड़े-जूते

मुंबई। एक जनवरी 2022 से कपड़े और जूते महंगे होने वाले हैं। क्योंकि इनमें लगने वाले जीएसटी को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों से सात फीसदी अधिक टैक्स देना होगा। इसका असर आम व्यक्तियों की जेब पर पड़ना स्वाभाविक है। यह जीएसटी एक हजार रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर लागू रहेगा। एक हजार रुपये के अधिक के कपड़े और फुटवियर पर पहले से 12 फीसदी टैक्स था। सरकारी अधिसूचना के अनुसार एक जनवरी 2022 से यह लागू कर दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में मानें तो यदि कोई ग्राहक एक हजार रुपये के जूते पर पचास रुपये टैक्स देता था। अब उसे बतौर टैक्स 120 रुपये चुकाने होंगे। ऐसा ही कपड़ों के कारोबार में भी होगा। दूध के कपड़ा कारोबारी से लेकर फुटवियर के काम से जुड़े व्यापारी इससे नाराज हैं। जीएसटी का टैक्स अधिक होने पर कपड़े और फुटवियर के दामों में भी इसका असर पड़ेगा।



व्यापारियों ने कहा टैक्स बढ़ाना सही नहीं...

व्यापारियों का तर्क है कि यदि जीएसटी में सुधार करना ही था तो टैक्स को पांच फीसदी ही कर देना चाहिए था। न कि पांच से बढ़ाकर 12 फीसदी करनी की जरूरत थी। जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से कई बार जीएसटी काउंसिल में फुटवियर और कपड़े की इंटेंड इयूटी का मामला उठ चुका था। कच्चे माल पर जीएसटी की दर 12 से 18 फीसदी थी। जबकि नैयार माल पांच फीसदी की दर से बिकता था। इससे उद्योगपतियों को सरकार से जीएसटी रिफंड लेना होता था। उनकी आईटीसी जमा होती रहती थी। रिफंड लेने में भी दिक्कतें आती थी। यदि इंटेंड इयूटी की समस्या का हल निकालना ही था तो सरकार को कच्चे माल पर टैक्स की दर को कम करना था। जिस प्रकार से टैक्स को बढ़ाया गया है वह अच्छा कदम नहीं है। इससे छोटे व्यापारियों के अलावा ग्राहकों को भी मंहवाई का सामना करना पड़ेगा।

सीएम उद्धव ठाकरे के पत्र से नाराज हुए राज्यपाल बोले - धमकी भरी भाषा में लिखी चिट्ठी

मुंबई: विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार और राजभवन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से लिखी गई चिट्ठी से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी) बहुत नाराज हो गए हैं। बता दें कि सीएम ने राज्यपाल को लिखे पत्र में वर्तमान विधान सभा सत्र में अध्यक्ष का चुनाव कराने की मंजूरी मांगी थी। राज्यपाल ने पत्र की भाषा धमकी भरी होने की बात कही है।

को लेकर नाराजगी विधान सभा अध्यक्ष पद के चुनाव कराने के संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर 27 और 28 तारीख को चुनाव कराने की स्वीकृति मांगी थी, जिस पर राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेकर उत्तर देने की बात कही थी। लेकिन बावजूद उसके दूसरा पत्र तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन पर भेजा गया, जिसके जवाब में राज्यपाल ने सीएम के पत्र की भाषा और उसके स्वर



नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कि इससे उन्हें दुख हुआ है।

बता दें कि विधान सभा स्पीकर के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र

सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव चल रहा है। महाराष्ट्र के

राज्यपाल ने स्पीकर के चुनाव प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने नियम समिति के माध्यम से स्पीकर चुनाव कराने का तरीका बदल दिया था।

इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव को असंवैधानिक बताया था। पिछले साल से खाली है स्पीकर का पद महाराष्ट्र विधान सभा में स्पीकर का पद पिछले साल से खाली है।

मालेगांव विस्फोट मामले में अब एटीएस की जांच की ही जांच होनी चाहिए: सुनील देवधर



मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने मालेगांव विस्फोट कांड की जांच के दौरान एटीएस द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)

के नेताओं को फंसाने की साजिश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब इस खुलासे के बाद एटीएस की जांच की जानी चाहिए। मालेगांव में 2008 में हुए

विस्फोट कांड के एक गवाह ने विशेष एनआइए कोर्ट को बताया कि उसे एटीएस के अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ सहित संघ के चार अन्य नेताओं को फंसाने का दबाव डाला था। इन चार नेताओं में सुनील देवधर का नाम भी शामिल था। बुधवार को मुंबई में सामाजिक संगठन माई होम इंडिया के एक वन इंडिया अवार्ड समारोह से पहले पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सुनील देवधर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा लोगों को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया जाता रहा है। मालेगांव कांड के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। अब एटीएस द्वारा रची गई इस साजिश का खुलासा होने के बाद उसकी पूरी जांच प्रक्रिया की ही जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 में हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले की

जांच में एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टीनेंट कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, अजय राहिलकर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी एवं सुधाकर चतुर्वेदी को आरोपित बनाया था। साध्वी प्रज्ञा फिलहाल भोपाल से सांसद हैं।

वह कई बार बयान देकर एटीएस अधिकारियों द्वारा अपने साथ की गई बर्बरता की कहानी बता चुकी हैं। इस मामले की जांच पहले एटीएस कर रही थी। तब एटीएस ने करीब 220 गवाहों के बयान दर्ज किए थे, लेकिन जांच केंद्रीय एजेंसी एनआइए के हाथ में आने के बाद अब तक 15 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं। इन्हीं में से एक गवाह ने एनआइए कोर्ट को पांच पृष्ठों का पत्र लिखकर बताया कि एटीएस ने उस पर योगी आदित्यनाथ, संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, सुनील देवधर, काकाजी व स्वामी असीमानंद को जबरन फंसाने का दबाव डाला था।

महाराष्ट्र में कोरोना के 2510 नए मामले बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता



मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई में बुधवार को कोरोना के 2510 नए मामले सामने आए। इस बीच, कोरोना से एक की मौत हुई और 251 ठीक हुए। इससे पहले महाराष्ट्र के

कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले हफ्ते हम प्रतिदिन 150 मामले दर्ज कर रहे थे, अब हम प्रति दिन लगभग 2000 मामले दर्ज कर रहे हैं। मुंबई में प्रतिदिन 2000 मामले हो सकते हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के दो हजार से ज्यादा केस पाए गए

हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में करीब 1400 मामले हैं। वहीं, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और इसे ह्यखतरनाक स्थिति करार दिया। टोपे ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में लोगों और अधिकारियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने और संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले आठ-10 दिनों में राज्य में सक्रिय मामले 5000-6000 के बीच रहे हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, 10 दिसंबर को राज्य में 6543 सक्रिय मामले थे। मंगलवार को राज्य में 11492 सक्रिय मामले थे।



अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया पूरा आरोप पत्र

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरा आरोप पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निषेध अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई से जुड़ी विशेष अदालत के समक्ष 7,000 पेज का आरोप पत्र दायर किया। इस आरोप पत्र में देशमुख के बेटों को भी आरोपित बनाया गया है। ईडी ने इससे पहले देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी) संजीव पलादे और निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने देशमुख को

इस साल एक नवंबर को संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा इस साल 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी का मामला यह है कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के माध्यम से मुंबई के कई बार व रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये की वसूली की थी।

महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोरोना संक्रमित

मुंबई: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं। सुप्रिया सुले ने बुधवार को ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना परीक्षण कराएं। गौरतलब है कि देश में ओमिक्रोन वैरिएंट का दायरा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पुडुचेरी में भी इसके दो मामले मिले और इसको मिलाकर अब तक नया वैरिएंट 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 मामले सामने आ चुके हैं और दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 165 केस मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा सात सौ के करीब पहुंच गया है। पुडुचेरी में मिले दो मरीजों में से एक 80 साल के व्यक्ति और दूसरी 20 साल की लड़की है। देश में ओमिक्रोन वैरिएंट के

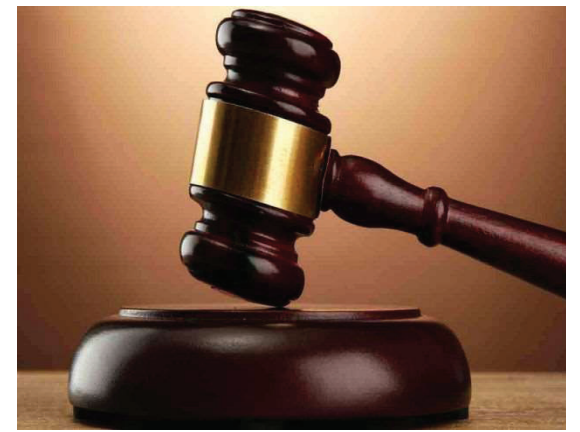


मामलों की संख्या बढ़कर 698 हो गई है। इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा गुजरात में 78, केरल में 64, तेलंगाना में 62 और राजस्थान में मिले 46 केस शामिल हैं। ओमिक्रोन के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश

व दिल्ली समेत कई राज्यों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में फिलहाल स्थिरता नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से छह से सात हजार के बीच संक्रमण के नए मामले मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 6,358 नए केस मिले हैं और 293 लोगों की जान गई है, जिनमें 236 मौतें केरल और 21 मौतें महाराष्ट्र से ही

हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में दो हजार से ज्यादा केस पाए गए हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में करीब 1,400 मामले हैं एक दिन पहले 809 मामले मिले थे। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड संक्रमित हो गई हैं। सांगली जिले में सरकारी मेडिकल कालेज में भी 49 छात्राओं को संक्रमित पाया गया है।

महाराष्ट्र में दस्तावेज लीक मामले में मुंबई कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा झटका



मुंबई। राज्य खुफिया विभाग (एसआइडी) से दस्तावेज लीक मामले में मुंबई किला कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले से जुड़े दस्तावेज और पेन ड्राइव 10 दिन के भीतर मुंबई पुलिस की साइबर सेल को सौंपने का आदेश दिया है। आइपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला के कार्यकाल के दौरान एसआइडी से दस्तावेज लीक होने के मामले की साइबर सेल सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जांच कर रही है। साइबर सेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज और पेन ड्राइव देने की मांग थी,

जिसे मंत्रालय ने नकार दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा की गई मांग बहुत अस्पष्ट है, क्योंकि वह पहले से ही जानती है किस तरह के दस्तावेज हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने अक्टूबर में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि इस मामले में फडनवीस मुख्य गवाह भी हैं, लेकिन वह समन जारी होने के बाद भी साइबर सेल के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। हालांकि, फडनवीस ने मिड-डे से बातचीत में कहा कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है, लेकिन साइबर सेल ने कुछ सवाल पूछे हैं जिनका जवाब वह उचित समय पर देंगे।

शीतकालीन सत्र में भी नहीं हो सका महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव शीतकालीन सत्र में भी नहीं हो सका। तीन दलों की पूर्ण बहुमत वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में यह पद पिछले तीन विधानमंडल सत्रों से नहीं भरा जा पा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार शीतकालीन सत्र में ध्वनिमत से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना चाहती थी। इसके लिए उसने विधायी नियमों में परिवर्तन भी किया। सरकार का तर्क था कि ऐसा करके विधायकों की खरीद-फरोख्त यानी हार्स ट्रेडिंग से बचा जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडल से यह प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने रविवार को राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी



से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पत्र सौंपा था। जिस पर राज्यपाल ने तुरंत कोई उत्तर न देते हुए विशेषज्ञों की राय

लेकर बात में सूचित करने को कहा था। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं साखोली विधानसभा सीट से विधायक नाना पटोले ने विधानसभा को

बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उनके अनुसार राज्यपाल ने अभी तक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भेजे

गए ध्वनिमत से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। बता दें कि गठबंधन सरकार ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, यानी 28 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने की योजना बनाई थी। लेकिन राज्यपाल द्वारा इसकी मंजूरी न दिए जाने से सरकार की यह योजना खटाई में पड़ गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस के हिस्से में आया था, और साखोली से चुने गए विधायक नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष बने थे। लेकिन चार फरवरी, 2021 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया

था। उसके बाद 10 महीनों से महाराष्ट्र विधानसभा में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। तब से विधानमंडल के तीन सत्र भी बीत चुके हैं। महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों को मिलाकर 170 विधायक हैं। इसके बावजूद सरकार गुप्त मतदान के जरिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने से झिझक रही है। जबकि आज फिर यह चुनाव न हो पाने से खीझे शिवसेना नेता संजय राऊत का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना विधानसभा का अधिकार होता है। इसके बावजूद अगर राज्यपाल रुकावटें डालते हैं, तो उससे लगता है कि उनपर कोई दबाव है।



संपादकीय

संपादक: गुर्तेजा मामाजीवाल

सतर्कता बढ़ाने का समय

कोरोना वायरस के बदले हुए रूप ओमिक्रोन का खतरा किस तरह बढ़ता चला जा रहा है, इसका प्रमाण है प्रधानमंत्री की ओर से की गई समीक्षा बैठक। ऐसी कोई बैठक इसलिए आवश्यक थी, क्योंकि देखते ही देखते ओमिक्रोन के संक्रमण से ग्रस्त मरीजों की संख्या 2510 पार कर गई है। ओमिक्रोन का संक्रमण 16 राज्यों तक पहुंच गया है। यह वायरस जिस तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, उसे देखते हुए इसकी आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में इसके मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ यूरोपीय देशों में ओमिक्रोन के संक्रमण की गति को देखते हुए भारत को कहीं अधिक सावधान रहना होगा। हालांकि जिस दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रोन पनपा, वहां इसके मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी यह मानकर नहीं चला जा सकता कि जैसा यूरोपीय देशों में हो रहा है, वैसा भारत में नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को नए सिरे से सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यह सही है कि ओमिक्रोन को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके संक्रमण के खतरे को देखते हुए कुछ राज्यों ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर होने वालों आयोजनों पर रोक लगाने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यदि ऐसे कदम उठाने का सिलसिला कायम रहा तो आगे चल कर ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जो आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत असर डालें। ऐसे फैसलों की नौबत न आने पाए, इसके लिए सरकारों को भी सचेत रहना होगा और आम लोगों को भी। यह ठीक है कि करीब साठ प्रतिशत बालिगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक टीके की एक भी खुराक नहीं ली, उनका टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। इसी के साथ इसका आकलन करने की भी आवश्यकता है कि मौजूदा टीके ओमिक्रोन से बचाव में मदद करेंगे या नहीं? इस बारे में भी फैसला करने का समय आ गया है कि बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं? भारत में बूस्टर डोज के इस्तेमाल की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में ही टीके की दोनों खुराक ले ली थीं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का अंदेशा है। इस अंदेशो को दूर करने के साथ ही ओमिक्रोन पर प्रभावी टीके के निर्माण का काम तेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण के संबंधित सवाल का भी जवाब खोजा जाना चाहिए।



कृषि कानूनों को फिर से लाना 2024 से पहले असंभव

मोदी है तो मुमकिन है का लोकप्रिय नारा विपक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहा है और विपक्ष भी ऐसा कि इसी नारे की कालिख सत्ता के मुंह पर पोतकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटी है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की गरमागरमी के बीच एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि जिन तीन कृषि कानूनों को हाल ही में रद्द किया गया है सरकार उसे फिर से ला सकती है। दरअसल, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने हालिया भाषण में कुछ ऐसा बोल गए जिसे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बड़े मुद्दे के तौर पर उछाल दिया है। अब कृषि मंत्री तोमर घूम-घूम कर सफाई देते फिर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है। यह विपक्ष की धिनौनी राजनीति है। दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री पिछले दिनों महाराष्ट्र के उस शहर में थे जो भाजपा की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। इस शहर से सत्ता का कोई भी बयान जारी होता है तो उसके मायने निकाले जाते हैं। ऐसा ही हुआ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने जो बात

कही उसे ध्यान से पढ़िए और शब्दों पर गौर कीजिए हहम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे। कुछ लोगों को रास नहीं आया। लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं। आगे फिर बढ़ेंगे क्योंकि हिन्दुस्तान का किसान हिन्दुस्तान की बैक बोन है। असल में जब आप मंत्री जी के भाषण का वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हहम एक कदम पीछे हटे हैं। आगे फिर बढ़ेंगे इस वाक्य को बोलने के दौरान मंत्री जी के चेहरे पर जो भाव था और जिस तरह की उत्तेजना झलकी वह इस बात को इंगित करने के लिए काफी है कि कोई इस भ्रम में न रहे कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को सदा के लिए रद्द किया है। उसे सत्ता अपने फायदे के लिए स्थगित किया है। वक्त निकल जाने के बाद उसे फिर से लाया जा सकता है। मतलब साफ है- मोदी है तो मुमकिन है। बस इसी मुद्दे को चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी देश को यह बताने और समझाने में जुट गई है कि सरकार किसानों को चुनौती के अंदाज में कह रही है कि हहआंदोलन को खत्म करना था लिहाजा हम थोड़ा पीछे हटे हैं। इस भ्रम में मत रहना कि हम तम्हारे

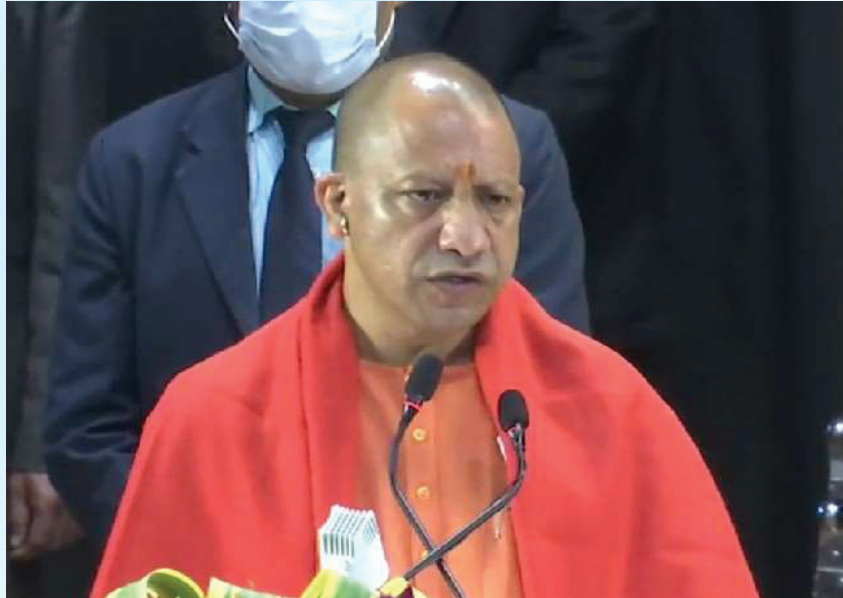
साथ खड़े हो गए हैं। हह कांग्रेस ने सरकार पर पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानूनों को वापस लाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तोमर के इस बयान को पीएम मोदी की माफी का अपमान करार देते हुए कहा कि सरकार ने इन विवादास्पद कानूनों पर यदि फिर से अपने कदम आगे बढ़ाए तो देश का किसान फिर सत्याग्रह करेगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे! अगर आपको याद हो तो गाजीपुर बॉर्डर छोड़ने से पहले भारतीय किसान आंदोलन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन अभी स्थगित हुआ है। हम फिर वापस आएंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ तीन कृषि कानूनों की ही वापसी हुई है। फसलों की एमएसपी का असली मुद्दा तो अभी बचा ही हुआ है जिसपर सरकार को फैसला करना है। कृषि मंत्री के खलबली मचाने वाले बयान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने भी चेतावनी दे दी कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। टिकैत की यह चेतावनी भी कोई ऐसी-वैसी जगह नहीं, किसानों के गढ़ और राजेश पायलट की कर्मभूमि

राजस्थान के दौसा में मीडिया के बीच जारी की। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ तीन कृषि कानून ही रद्द किए हैं, किसान संगठनों की अन्य मांगें अभी नहीं मानी गई हैं। सत्ता पक्ष टिकैत के बयान को भले ही हथोथा चना बाजे घनाहू के अंदाज में ले रही हो, लेकिन किसान आंदोलन को करीब से समझने वाले विश्लेषक इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि टिकैत की प्रतिक्रिया को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे भी तोमर का व्यक्तित्व गंभीर किस्म का है। लिहाजा उनके बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी गंभीर व्याख्या होनी चाहिए ताकि इस बात का पता चल सके कि अगर फिर से कृषि कानून लेकर सरकार आती है तो उसका स्वरूप क्या होगा? हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोई इकलौते नेता नहीं हैं जिन्होंने कृषि कानूनों को फिर से लाने की तरफ इशारा किया हो। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज भी कह चुके हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की वजह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। बिल का क्या है? बनता है, बिगड़ता है। फिर वापस आ जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कुछ इसी तरह के संकेत देते हुए कह चुके हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूलों के अनुदेशकों व रसोइयों को दिया नए साल का उपहार

लखनऊ: ठंड के मौसम में एक ओर बारिश ने ठिठुरन बढ़ाई तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपहारों की बरसात करके चार लाख अनुदेशकों व रसोइयों की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी है। सीएम योगी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का 2000 रुपये और रसोइयों का 500 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। नए वर्ष का उपहार देते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की तर्ज पर अब रसोइयों को भी हर साल दो साड़ी मिलेगी और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा।

इसके अलावा एप्रन व हेयर कैप की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी कंवेशन सेंटर में बुधवार को विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये अनुदेशक, रसोइयों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से संवाद करते हुए अल्प मानदेय, घर से दूर तैनाती की पीड़ा साझा करते हुए मानदेय बढ़ोतरी की मांग की। सभी का दर्द सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विद्यालयों के सुधार में अनुदेशकों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था के तहत अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी, अलग-अलग कारणों से वह वर्ष 2009 में खंडित हो गई। लेकिन, प्रदेश सरकार



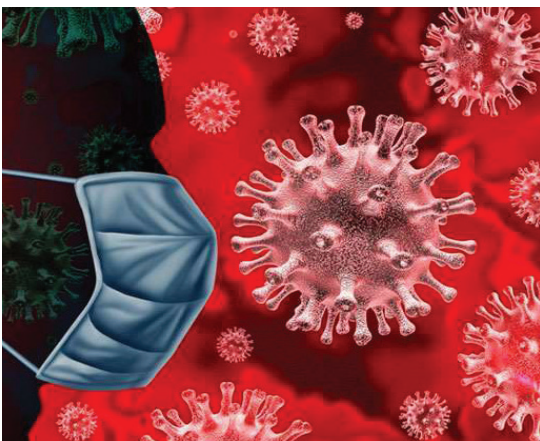
ने किसी की सेवाएं समाप्त नहीं कीं। मात्र 7,000 रुपये के मासिक मानदेय को बढ़ाये

जाने की मांग को वाजिब बताते हुए सीएम ने इसमें 2,000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी

कर इसे सम्मानजनक स्तर पर ले जाने की घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों

की सेवाओं को व्यवस्थित करने का भरोसा दिलाते हुए आवश्यक कदम उठाने के लिए विभाग को निर्देशित किया। वहीं रसोइयों के कार्यदायित्व की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में रसोइयों का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक किया गया था। अब कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए एक बार फिर इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। रसोइयों के बैंक में खाते खुलवाए जाएंगे, मानदेय व अन्य धन उसी में आएगा। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश चंद्र द्विवेदी, प्रमुख सचिव दीपक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह आदि मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या, बुधवार को आए 118 नए केस



लखनऊ: यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 118 नए रोगी मिले। बीते दो दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में तीन गुणा की बढ़ोतरी हुई है। 27 दिसंबर को 40 मरीज मिले थे। वहीं साढ़े पांच महीने बाद एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोगी मिले हैं। बीते सात जुलाई को इससे ज्यादा 120 मरीज मिले थे। नए मिले मरीजों के मुकाबले 36

रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब सक्रिय केस बढ़कर 473 हो गए हैं। प्रदेश में जो 118 नए रोगी मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा 25 लखनऊ में मिले हैं और 21 रोगी गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि वह कोरोना से बचाव के लिए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करें। दो गज की शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन

करें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में दो लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच कराई गई। कोरोना जांच की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इससे पहले सोमवार को 1.42 लाख और मंगलवार को 1.93 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। तक कुल 9.25 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। अब तक प्रदेश में कुल 17.10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 16.87 लाख रोगी ठीक हो चुके हैं। अब रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत है और पाजिटिविटी रेट 1.86 प्रतिशत है। इस समय सबसे ज्यादा कुल 99 मरीज गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पर लखनऊ में 90 और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद में 75 मरीज हैं।

ओमिक्रोन के कारण यूपी में बंद हो सकते हैं स्कूल

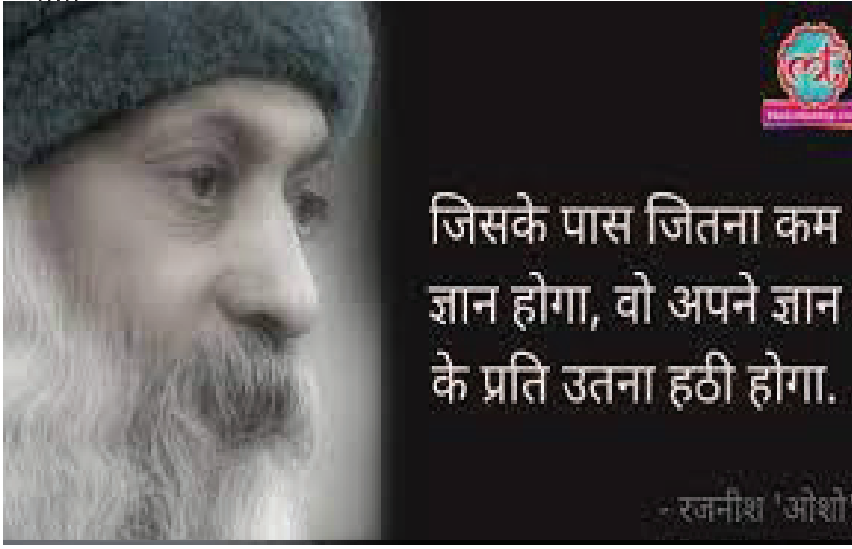


बरेली: कोरोना की दो लहरें झेलने के बाद हर इंसान घबराया हुआ है। विदेश में ओमीक्रोन के मामले सामने आने के बाद इसका असर शहर के स्कूलों में भी दिखने लगा है। पिछले 10-15 दिनों में स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने लगी है। वहीं शिक्षा विभाग भी इसको लेकर सतर्क हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने भी स्कूल प्रबंधन को फिर

आनलाइन पढ़ाई की तैयारी शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। ताकि समय पर ही सारा पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके और पढ़ाई प्रभावित न हो। शासन ने संयुक्त शिक्षा निदेशक और डीआइओएस को पत्र के जरिए निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल प्रबंधन को निर्देशित कर अब छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल में प्रवेश दें। साथ ही विद्यालयों में

प्रवेश और कक्षाओं के दौरान समय-समय पर सैनिटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) ने बताया कि स्कूल में छात्रों को संक्रमण से बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो इसको लेकर फिलहाल स्कूल प्रबंधन को पूर्व में शासन से जारी कोविड गाइडलाइन का ही पालन करना है।

कविता



जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा, वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही होगा.

- रजनीश 'ओशो'

कहै कबीर दीवाना-ओशो

इतना ही फर्क है, भक्त और ज्ञानी में। भक्त परमात्मा को मांगता है, ज्ञानी उतना भी नहीं मांगता। इसलिए ज्ञान से ऊंची भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति द्वार तक पहुंचा देती है। लेकिन आखिरी क्षण में भक्ति को भी खो जाना पड़ता है। क्योंकि तभी मिलन पूरा होता है। जब परमात्मा की मांग भी छूट जाती है। क्योंकि उतनी मांग भी तो परमात्मा और तुम्हारे बीच में बनी रहेगी। उतनी मांग भी नहीं चाहिए। नास्तिक वही है, जो वस्तुओं से घिरा है। इसलिए पश्चिम नास्तिक है। इसलिए नहीं, कि वहां लोग परमात्मा को नहीं मानते। तुमसे ज्यादा लोग चर्च जाते हैं। हिंदुओं के पास तो मंदिर जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जाओ, न जाओ। जब मौज हो, जाओ। लेकिन ईसाइयों में तो व्यवस्था है कि रविवार जाना ही है। अगर तुम मंदिरों की कोई जांच करें मंगल ग्रह से आकर, तो सदा उनको खाली पाएगा। या कभी इक्के दुक्के आदमी आते हुए जाते हुए मालूम पड़ेंगे। किसी की पत्नी बीमार है, आना पड़ा। जारी.....

सर्दियों में ब्लड क्लॉटिंग (नसों में खून जमने) से बचने के लिए पिएं ये 5 तरह के जूस



सर्दियों के दिनों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ब्लड क्लॉटिंग

है। इस समस्या से बचने के लिए आपको ठंड के दिनों में अपनी डाइट में कुछ हेल्दी जूस को एड करना चाहिए। ये आपकी सेहत को अच्छा तो रखेंगे ही साथ ही आपकी बाँडी को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से भी बचाएंगे। ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में वटामिन के रचि वेजिटिबल और फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए। ज्यादातर हरी सब्जियों में वटामिन के पाया जाता है जैसे पालक आपको ठंड के दिनों में पालक के जूस का सेवन करना चाहिए।

यानी खून के थक्के जमने की समस्या से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता

फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप

83 फिल्म के रिलीज से पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी साबित होगी. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफलता के झंडे गाढ़ेगी. वहीं मेकर्स को भी आस थी कि इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस कारोबार काफी ज्यादा होगा लेकिन तमाम दावों और उम्मीद के बावजूद फिल्म ढेर हो गई. इतना ही नहीं फिल्म को फ्लॉप करार दिया जा रहा है और बात की सबसे बड़े नुकसान की तो इस बात की गाज गिरी है फिल्म के लीडिंग स्टार रणवीर सिंह पर. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो रणवीर की फीस में से अब कटौती होने वाली

है. जबकि कुछ समय पहले खबर आई थी कि हालिया ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी

उन्हें फीस तक लाले पड़ गए हैं. 250 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म महज 58



लगातार बढ़ती फैन फॉलोइंग को देखते हुए रणवीर डबल-फिगर में चार्ज करने वाले हैं. फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह ने मेकर्स से 20 करोड़ फीस के अलावा प्रॉफिट में भी हिस्सा मांगा है पर जिस तरह से फिल्म फ्लॉप हुई हुई

करोड़ के करीब ही पहुंच पाई. जिस तरह से फिल्म 83 का ग्रैंड प्रीमियर रख गया था और फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट के सितारों का भी मेला लगा रहा था उससे लगा था फिल्म सुपर धमाल मचाएगी.

Begin your Journey to a Better Life
With Peace, Love, & Happiness

YOGA

YOGA classes available
Offline & Online

Session 5 days a week

FREE TRIAL CLASS

C- 505, Badri bldg, Mathuradas road, Kandivali (W), Mumbai- 400067.

YOGA BY ZAINAB
70213 01200

ICON OPTICAL GALLERY

- Buy 2 Prs of prescription Antireflection glasses of Rs 1600/- and get 2 frames free.....
- Buy 2 Prs of Blue Cut Antireflection prescription glasses of Rs 1899/- and get 2 frames free.....
- Buy 1 Frame or Sunglass & get 1 Frame or Sunglass free Rs 1000/- onwards.....
- Branded Frames, Sunglasses & Glasses available with discount.
- We make any Single Vision, Bifocal and Progressive prescription Glasses in 1 or 2 hrs.

9819292152
murtaza12152@yahoo.com

Shop No. 52, R.N.A. Arcade, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai - 400 053

अब इस खिलाड़ी की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनने वाली पूर्व दिग्गज ने बताया खिलाड़ी हैं मौजूद

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में खेल रही है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक बार फिर से इस मैच में निराश करने वाली रही। दोनों ही पारी में बड़े बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने टीम को निराश किया। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने पुजारा की जगह को लेकर बात की है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज पुजारा के फार्म को लेकर काफी बातें की जा रही हैं। सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में वह बिना खाता खोले वापस लौटे थे जबकि दूसरी पारी में भी महज 16 रन ही बनाए। साल 2019 में आस्ट्रेलिया के दौरे पर सिडनी में आखिरी बार शतकीय पारी खेली थी। मदन ने उनकी टीम में जगह पर सवाल उठाते हुए कहा खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनको प्लेइंग इलेवन से बाहर कर



सकते हैं। पुजारा संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस टीम में ऐसे काफी खिलाड़ी हैं जो उनको प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकते हैं। तीसरे नंबर तो कप्तान को भी एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो पारी को संभाल कर सक सके और ज्यादा से ज्यादा रन भी टीम के बनाकर दे

सके। एक वक्त था जब पिच पर पुजारा ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया करते थे। तो यह बात एक दम से साफ है कि वह इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। रहाणे ने सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में महज दो रन से अर्धशतक से चूक गए थे। 102 गेंद का सामना करते हुए उन्होंने 48 रन बनाए

थे। वहीं दूसरी पारी में वह 20 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने महज 23 गेंद का ही सामना किया था। खराब फार्म से गुजर रहे इस खिलाड़ी को हाल ही में टेस्ट की उप कप्तानी से हटाया गया। रोहित शर्मा को उनकी जगह साउथ अफ्रीका दौरे से पहले यह जिम्मेदारी दी गई थी।

सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, साउथ अफ्रीका के 94 रन पर गिरे 4 विकेट



नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। बुधवार 29 दिसंबर को मुकाबले के चौथा दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 130 रन की बढ़त और दूसरी पारी में 16/1 से आगे खेलते हुए 174 रन पूरी टीम आल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के सामने भारत ने मैच जीतने के लिए 305 रन की लक्ष्य रखा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ

अफ्रीका ने चार विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाए थे। जीत के लिए आखिरी दिन भारत को 6 विकेट की जरूरत होगी जबकि मेजबान टीम को 211 रन हासिल करना होगा। भारतीय टीम चौथे दिन दूसरी पारी में 174 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 305 रन का लक्ष्य मिला। मेजबान के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले शमी ने दूसरी पारी में मेजबान को पहला झटका दिया। एडन मारक्रम 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ट होकर वापस लौटे।

टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन का धमाका जारी



नई दिल्ली। आइसीसी ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की जिसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले गेंदबाज स्काट बोलैंड ने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में जगह बनाई है। भारतीय आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की बुधवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में गेंदबाजों और आलराउंडरों की सूची में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। रवींद्र जडेजा टेस्ट आलराउंडरों की सूची में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली ने भी बल्लेबाजों की सूची में क्रमशः पांचवां और सातवां स्थान बरकरार रखा है। रोहित के 797 और कोहली के 756 अंक हैं। बल्लेबाजों की सूची में आस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने (915 अंक) शीर्ष पर काबिज हैं।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया मुश्किल लक्ष्य

नई दिल्ली। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 305 रन का मुश्किल लक्ष्य देने के बाद शुरू में ही उसे एक झटका देकर पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन बुधवार को यहां चाय के विश्राम तक अपना पलड़ा भारी रखा। भारत की दूसरी पारी 174 रन पर खत्म हुई, जिससे दक्षिण अफ्रीका को चार सत्र से अधिक समय में जीत के लिए 300 से अधिक रन बनाने की चुनौती मिली। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 197 रन पर आउट करके 130 रन की बढ़त हासिल की थी। सेंचुरियन में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकार्ड इंग्लैंड के नाम पर है जिसने 2000-01 में चौथी पारी में 251 रन बनाकर जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका ने चाय के विश्राम तक अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 22 रन बनाए और वह लक्ष्य से 283 रन



पीछे थी, जबकि भारत को जीत के लिए नौ विकेट और झटकने की जरूरत थी। मुहम्मद शमी ने जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद संभाली और अपनी तीसरी गेंद पर ही एडेन मार्करैम (1) को बोल्ट करके दक्षिण

अफ्रीकी खेमे में कड़ा संदेश भेजा। चाय के विश्राम के समय कप्तान डीन एलगर नौ और कीगन पीटरसन 12 रन पर खेल रहे थे। इससे पहले भारत की तरफ से दूसरी पारी में रिषभ पंत ने सर्वाधिक 34

रन बनाए, जबकि उसके बाद दूसरा बड़ा स्कोर अतिरिक्त रन (27) का था। दक्षिण अफ्रीका के लिए कैगिसो रबादा और मार्को जेनसेन ने क्रमशः 42 और 55 रन देकर चार-चार विकेट झटके।

